



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 19 मई, 2001/29 वैशाख, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अप्रैल, 2001

संख्या जी० ए० डी-सी(पी० ए०) 4-1/95-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल,¹ हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (अधिनियम, 1971) (1971 का 4) की धारा 7 और 7अ के साथ पठित धारा-13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (मोटरकार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) नियम, 2001 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ से विरुद्ध न हो,—

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 अभिप्रेत है ;

(ख) “अध्यक्ष/उपाध्यक्ष” से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

- (ग) "सम्परीक्षा अधिकारी" से महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (ङ) "मन्जूरी प्राधिकारी" से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अभिप्रेत है ; और
- (च) शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वहीं अर्थ होंगे जो अधिनिर्णय में क्रमशः उनके हैं ।

मोटर कार अग्रिम

3. अनुज्ञेय जब अग्रिम होगा.—अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को यथास्थिति मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम संदत्त किया जा सकेगा ताकि वह अपने कार्यालय के कर्तव्यों का, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सुविधापूर्वक तथा दक्षणापूर्वक निर्वहन कर सके ।

4. अग्रिम की अधिकतम रकम.—मोटर कार के क्रय हेतु यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अधिकतम राशि दस लाख रुपये या खरीदी जाने वाली मोटर कार की वास्तविक कीमत, जो भी हो, से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण नियम, 2000 के नियम 13 या इन नियमों के नियम 13 के अधीन या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1979 के नियम 4 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया हो तो मोटर कार अग्रिम की कुल राशि की परिसीमा यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, द्वारा पहले लिए गए भवन निर्माण सहित दस लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने मन्त्री, या विधान सभा सदस्य, यथास्थिति की हैमियत में मोटरकार अग्रिम ले रखा हो तो मोटर कार की कुल राशि की परिसीमा उसे पहले दिए गए मोटर कार अग्रिम सहित दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी ।

5. अग्रिम की वसूली.—(1) नियम 4 के अधीन मंजूर अग्रिम की वसूली उस पर व्याज सहित 180 समान मासिक किस्तों में की जाएगी सरकार शेष पदावधि को ध्यान में रखते हुए या यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष स्वयं ऐसा चाहें तो कम संख्या की किस्तों में वसूली के आदेश कर सकेगी । कटौती अग्रिम लेने के पश्चात् पहले जारी बतन से प्रारम्भ की जाएगी ।

(2) 3 दिसम्बर, 1993 को या इसके पश्चात् मंजूर किए गए ऋणों की बाबत 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज प्रभारित किया जाएगा:

परन्तु यह कि 3 दिसम्बर, 1993 से पूर्व मंजूर किए गए ऋण पर व्याज की दर अग्रिम के पूरे समय तक वही लागू रहेगी ।

(3) यदि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अग्रिम धनराशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही किसी कारणवश अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद पर नहीं बना रहता है परन्तु विधान सभा का सदस्य बना रहता है, तो मासिक किस्तें उसे विधान सभा सदस्य के रूप में अनुज्ञेय विभिन्न भत्तों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूल की जाएगी ।

(4) यदि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अग्रिम धनराशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं बना रहता है परन्तु पेंशन का हकदार होता है, तो उसे मिलने वाली पेंशन में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूली की जाएगी तथा मासिक किस्तों की बकाया राशि उसके द्वारा नियमित रूप से सरकारी कोष में जमा की जाएगी और इस भुगतान के प्रमाण के रूप में वह चालान की एक प्रति सरकार को नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा ।

(5) यदि वह विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं रहता तथा पेंशन का हकदार भी नहीं बनता तो उसके द्वारा मासिक किस्तें उस पर प्रोदभूत व्याज सहित नियमित रूप से प्रतिमास सरकारी कोष में जमा की जाएगी तथा इसके प्रमाण में कोष के चालान की प्रति सरकार को प्रस्तुत जायेगी ।

(6) अग्रिम धनराशि तथा उस पर प्रोदभूत व्याज की वसूली से पूर्व मृत्यु होने की दशा में यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा अग्रिम पर प्रोदभूत व्याज सहित अग्रिम की शेष राशि एक

मुश्त सरकारी कोष में जमा करेंगे और वे समस्त राशि के जमा किए जाने के प्रमाण में चालान की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत करेंगे ।

(7) यदि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उसका विधिक प्रतिनिधि, अग्रिम के मूलधन अथवा उस पर व्याज की मासिक किस्तों की नियमित अदायगी नहीं करता है या यदि वह दिवालिया हो जाता है/या ऋण की अदायगी के नियमों तथा शर्तों के अनुपालन या पालन करने में विफल रहता है तो उस दशा में ऋण की सम्पूर्ण मूल राशि या उसमें से इतना जितना कि उस समय देय तथा असदत्त रहा हो, सरकार को उस पर उप-नियम-(2) में विनिर्दिष्ट विहित दर से व्याज सहित एक मुश्त में तत्काल देय होगा । सरकार को उपरोक्त बकाया राशि को “भू राजस्व के बकाया” के रूप में वसूल करने की स्वतन्त्रता होगी । विधान सभा सचिवालय द्वारा इस प्रभाव में की गई वसूली उपरोक्त शर्तों पर विचार करते हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार के क्रय के लिए ऋण अग्रिम) नियम, 1979 जैसा समय-समय पर प्रवृत्त हो, के अधीन विनियमित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण.—मासिक रूप से वसूल की जाने वाली अग्रिम धनराशि की अन्तिम किस्त, जिसमें शेष राशि रुपये के किसी अंश सहित वसूल की जानी है, को छोड़कर पूरे रुपयों में नियत की जाएगी ।

6. मोटर कार का विक्रय.—(1) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद त्याग देने के सिवाय अग्रिम की सहायता से खरीदी गई मोटर कार को बेचने के लिए यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा सरकार की पूर्व मंजूरी ली जाएगी, यदि ऐसे अग्रिम का उस पर प्रोदभूत व्याज सहित पूर्णतः प्रतिसंदाय नहीं किया गया हो ।

(2) सभी मामलों में जब मोटर कार अग्रिम को उस पर व्याज सहित पूर्णतः प्रतिसंदाय से पहले ही बेच दी जाती है तो ऐसे बकाया अतिशेष के प्रतिसंदाय हेतु जहां तक अवश्य हो विक्रय आगम उपयोजित होगा :

परन्तु जब मोटर कार इसलिए बेची गई हो कि अन्य दूसरी मोटर कार खरीदी जा सकेगी सरकार यथा-स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को यथास्थिति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसी खरीद हेतु विक्रय आगम को प्रयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी, अर्थातः—

(क) परादेय राशि को नई कार की लागत से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं होगी ;

(ख) परादेय राशि का प्रतिसंदाय पूर्व नियत दर पर जारी रहेगा ; और

(ग) नई कार सरकार के पास बन्धक होगी और बीमाकृत भी होगी ।

7. अवधि जिसमें भीतर कार खरीदने के लिए वार्ता पूर्ण की जा सकेगी.—यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम लेता है खरीदने के लिए वार्ता पूर्ण करेगा और अग्रिम लेने की तारीख के एक महीने के भीतर मोटर कार के लिए पूर्ण अदायगी करेगा, ऐसी सम्पूर्ति और अदायगी न होने पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि उस पर एक महीने के व्याज सहित सरकार को वापिस की जाएगी । व्यक्तिगत मामलों की दशा में व्यवहार की सम्पूर्ति के लिए सरकार द्वारा एक महीने की अवधि का तथापि बढ़ाया जा सकेगा । जब मोटर कार पहले ही खरीदी गई हो और पूरा संदाय कर लिया हो अग्रिम अनुज्ञेय नहीं होगा । उस दशा में जिसमें अदायगी भागतः की हो तो अग्रिम की राशि असदत्त बकाया तक ही सीमित होगी जैसा यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।

8. करार का निष्पादन.—अग्रिम लेते समय यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रारूप-I में करार निष्पादित करेगा और खरीद पूर्ण होने पर जिसमें वह अग्रिम के लिए सरकार को प्रति भूति के रूप में मोटर कार को आङ्मान करते हुए प्रारूप-II में बन्धक पत्र निष्पादित भी करेगा । मोटर कार की लागत कीमत बन्धक पत्र के साथ संलग्न अनुसूचि के विनिर्देशों में दर्ज की जाएगी ।

9. संपरीक्षा अधिकारी को प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना.—जब अग्रिम लिया जाता है, मंजूरी प्राधिकारी, संपरीक्षा अधिकारी को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि यथास्थिति अग्रिम लेने वाले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने प्रारूप-II में करार को हस्ताक्षरित कर लिया है और यह नियमानुसार है । मंजूरी प्राधिकारी देखेगा कि मोटर कार, अग्रिम लेने की तारीख से एक महीने के भीतर या ऐसी अवधि में, जैसी नियम 7 के अधीन कारंवाई सम्पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा वैयक्तिक मामलों में विनिर्दिष्ट अनुज्ञात की जा सकेगी, खरीद ली गई है और प्रत्येक बन्धक-पत्र को तत्परता से संपरीक्षा अधिकारी को अन्तिम अभिलेख से पूर्व परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।

10. सुरक्षित अभिरक्षा और बन्धक पत्र को रद्द किया जाना.—बन्धक-पत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा । जब अग्रिम का, उस पर व्याज सहित, पूर्ण रूप में प्रतिसंदाय कर लिया जाता है तो

बन्धक-पत्र, मंजूरीदाता अधिकारी से अग्रिम और व्याज के सम्पूर्ण प्रतिसंदाय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके सम्यक् रूप से रद्द करके यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को वापिस किया जाएगा।

11. मोटर कार का बीमा.—अग्रिम से खरीदी गई मोटर कार का अग्नि, चोरी या दुर्घटना द्वारा पूर्ण हानि के विरुद्ध किसी साधारण बीमा कारबार करने वाली बीमा कम्पनी/बीमा निगम के साथ बीमा किया जाएगा। बीमा पॉलिसी में प्ररूप-III के अनुसार खंड होगा जिसमें निगम, मोटर कार की हुई हानि या क्षति, जिसकी प्रतिपूर्ति, मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है, की वाबत कोई राशि स्वामी की अपेक्षा; सरकार को देने का करार करती है। ऐसा बीमा ऋण की तारीख के एक महीने के भीतर प्रभावी होगा।

भवन निर्माण अग्रिम

12. अग्रिम राशि कब अनुज्ञेय है.—यथा स्थिति, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्रारूप-IV पर दिए गए आवेदन पर उनके समुचित जीवन स्तर का ध्यान रखते हुए अपना भवन निर्माण करने अथवा निर्मित भवन को खरीदने के लिए प्रतिदेय अग्रिम धनराशि दी जा सकती है।

13. अग्रिम की अधिकतम राशि.—यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को भवन निर्माण, निर्मित भवन को खरीदने के लिए अग्रिम की अधिकतम राशि दस लाख रुपये या वास्तविक कीमत या भवन निर्माण की लागत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यदि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने इन नियमों के नियम 4 के अधीन या हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम, 2000 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (मोटर कार अग्रिम ऋण) नियम, 1979 के नियम 4 के अधीन मोटर कार अग्रिम ले रखा हो तो भवन निर्माण अग्रिम की कुल राशि की परिसीमा यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि जहां यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने मन्त्री या विधान सभा सदस्य जैसी भी स्थिति हो, की हैमियत में भवन निर्माण अग्रिम ले रखा हो तो भवन निर्माण अग्रिम की कुल राशि की परिसीमा उसे पहले दिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

14. भुगतान की राशि.—इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अग्रिम राशि का भुगतान निम्नलिखित रीति में किया जाएगा:—

(1) अपने स्वयं के भवन निर्माण के लिए:

(क) पहली किस्त निर्माण आरम्भ करने के लिए स्वीकृत धनराशि के 50 प्रतिशत के बराबर।

(ख) दूसरी तथा अन्तिम किस्त जब भवन छत की सतह तक पूर्ण हो जाए स्वीकृत कुल अग्रिम धनराशि का शेष 50 प्रतिशत।

(2) नवनिर्मित भवन को खरीदने के लिए एक मुश्त राशि:

टिप्पण.—यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र अवश्य प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का प्रयोग उमी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह धनराशि उन्हें अग्रिम धन के रूप में दी गई थी यह प्रमाण-पत्र उन द्वारा राशि के उक्त प्रयोजन के लिए वास्तविक प्रयोग हेतु पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा।

15. अग्रिम धनराशि की वसूली.—(1) नियम 13 के अधीन स्वीकृत अग्रिम धनराशि तथा उस पर प्रोदभूत व्याज की वसूली 180 ममान मासिक किस्तों में की जायेगी। सरकार शेष कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि स्वयं ऐसा चाहे तो कम किस्तों में वसूली का आदेश दे सकती है। कटौती प्रथम किस्त/या एक मुश्त अग्रिम राशि प्राप्त करने के पश्चात् लिए जाने वाले वेतन से आरम्भ की जाएगी।

(2) 3-12-1993 को या इसके पश्चात् स्वीकृत राशि की वाबत पांच प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण व्याज प्रभारित होगा:

परन्तु 3-12-1993 से पूर्व स्वीकृत अग्रिम पर निम्न व्याज की दर अग्रिम के पूरे समय तक वही लागू रहेगी।

(3) यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अग्रिम धनराशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व ही किसी कारणवश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर नहीं बना रहता परन्तु विधान सभा सदस्य बना रहता है तो मासिक किस्त उसे विधान सभा सदस्य के रूप में मिलने वाले विभिन्न भत्तों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूल की जाएगी।

(4) यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अग्रिम धनराशि के पूर्ण प्रतिसंदाय होने से पूर्व किसी कारणवश विधान सभा सदस्य के पद पर भी नहीं बना रहता परन्तु पेंशन का हकदार होता है तो उसे मिलने वाली पेंशन में से विधान सभा सचिवालय द्वारा वसूली की जाएगी तथा मासिक किस्तों की बकाया राशि उसके द्वारा नियमित रूप से खजाने में जमा की जायेगी और इस भुगतान के प्रमाण के रूप में वह चालान की एक प्रति सरकार को नियमित रूप से प्रेषित करेगा।

(5) यदि वह विधान सभा सदस्य के पद पर नहीं रहता तथा पेंशन का हकदार भी नहीं बनता तो उसे मासिक किस्तें उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित नियमित रूप से प्रतिमास सरकारी खजाने में जमा करानी पड़ेगी तथा इसके प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को प्रेषित करनी पड़ेगी।

(6) अग्रिम धनराशि तथा इस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूली से पूर्व मृत्यु की दशा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विधिक प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा मासिक किस्त नियमित रूप में सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी जिसके प्रमाण में खजाने के चालान की प्रति सरकार को हर मास प्रेषित करनी होगी।

(7) यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उनका विधिक प्रतिनिधि अग्रिम धनराशि अथवा उस पर ब्याज की मासिक किस्त की नियमित अदायगी नहीं करता है या यदि वह दिवालिया हो जाता है या ऋण की अदायगी के नियमों तथा शर्तों के अनुपालन या पालन करने में विफल होता है तो इस दशा में ऋण की सम्पूर्ण मूलराशि या उस में से इतना जितना कि उस समय देय तथा असंदत रहा हो, सरकार को उस पर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज सहित एक मुश्त में तत्काल देय होगा। सरकार को उपरोक्त बकाया राशि को "भू-राजस्व के बकाया" के रूप में वसूल करने की छूट होगी।

स्पष्टीकरण.—मासिक रूप में वसूल की जानी वाली धनराशि अन्तिम किस्त जिसमें शेष राशि रुपये के किसी अंश सहित वसूल की जानी है को छोड़कर पूरे रूपों में नियत की जाएगी।

16. ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु बन्धक विलेख के निष्पादन का उत्तरदायित्व.—यथास्थिति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, यदि अग्रिम धन तथा उस पर संभूत ब्याज के पूर्ण परिशोधन होने से पूर्व ही निधन हो जाता है अथवा वह अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं रहता है तो उसके फलस्वरूप सरकार को होने वाली हानि से प्रतिभूत करने हेतु उस भवन को जो कि निर्मित किया गया अथवा खरीदा गया है को उसे, भूमि सहित जिस पर वह भवन है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप-V पर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास बन्धक किया जाएगा, जिसका निष्पादन पहली किस्त अथवा एक मुश्त राशि के भुगतान से पूर्व, यथास्थिति, किया जाएगा तथा देय राशि की पूरी अदायगी के पश्चात् बन्धक को इन नियमों में संलग्न प्रारूप-VI पर प्रति-हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन पर मुक्त किया जाएगा। बन्धक विलेख निष्पादन होने पर मंजूरी प्राधिकारी उस भूमि पर जिस पर उक्त भवन खड़ा है या उसे निर्मित करने का प्रस्ताव है आवेदक के हक की शुद्धता से अपने आप को सन्तुष्ट करेगा।

17. परिसर को अच्छी अवस्था में रखने तथा आग के जोखिम आदि के लिए बीमा कराने का दायित्व.—यथास्थिति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपने खर्चे पर भवन को अच्छी अवस्था में रखेगा तथा इसे सभी ऋण भारों से भी मुक्त रखेगा। वह इसका आग, बाढ़ आदि के लिए इतनी राशि तक बीमा करवाएंगे, जोकि स्वीकृत अग्रिम धनराशि से कम न हो, तथा इस प्रयोजन का वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

18. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1981 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात, या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमार्ग रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

प्ररूप-1

मोटर कार खरीदने के लिए अग्रिम लेते समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप
(नियम 8 देखें)

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री..... अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रणामक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिनी भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "हिमाचल प्रदेश" सरकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उतरवर्ती और समनुदेशिनी भी है) के बीच आज तारीख को किया गया है।

उधार लेने वाले ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (मोटर कार और भवन निर्माण अग्रिम) नियम, 2001 के अधीन मोटर कार खरीदने के लिए सरकार को रुपये (.....) के ऋण के लिए आवेदन किया है और सरकार इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट निबन्धनों और शर्तों पर उधार लेने वाले को उधार देने के लिए सहमत हो गई है।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उधार लेने वाले को रु0 (..... रुपये) की संदत्त राशि के प्रतिफल में पक्षकारों के बीच करार किया जाता है (उधार लेने वाला जिसकी पावती की अभिस्वीकृति करता है) उधार लेने वाला सरकार के साथ एतद्वारा करार करता है कि:—

- (1) जैसा कि उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित है उसे विधान सभा सदस्य के रूप में संदेय वेतन या भत्ते, पेंशन में मासिक कटौतियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार मंगणित व्याज सहित कथित राशि को सरकार को संदत्त करेगा (जितनी अधिक वसूल की जा सके और शेष उसके द्वारा सरकारी कोष में जमा की जाएगी) और सरकार को ऐसी कटौतियां करने को प्राधिकृत करता है। यदि उधार लेने वाला पेंशन का हकदार न हो तो प्रोदभूत व्याज सहित मासिक किम्न उसके द्वारा नियमित रूप से सरकारी कोष में जमा की जाएगी तथा वह सरकार को उक्त नियमों में यथा उपबन्धित जमा की गई राशि के साक्ष्य स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत करेगा ;
- (2) मोटर कार की खरीद में उक्त ऋण की पूर्ण राशि को व्यय करने या यदि संदत्त वास्तविक कीमत ऋण से कम हो तो उनके अन्तर का प्रतिसंदाय सरकार को इन विलेखों की तारीख से एक मास के भीतर तत्काल करेगा ; और
- (3) उधार लेने वाले को यथा पूर्वोक्त उधार दी गई राशि के लिए सरकार के पास प्रतिपूर्ति के रूप में उक्त मोटर कार के आड़मान करने वाले दस्तावेजों और उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित प्ररूप में व्याज का निष्पादन करेगा।

इसके द्वारा अन्त में यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि इन विलेखों की तारीख से एक महीने के भीतर पूर्वोक्त रूप में मोटर कार क्रय और आड़मान नहीं की जाती या उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या पद त्याग देता है अन्यथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नहीं रहता या उसकी मृत्यु हो जाती है ऋण की पूरी राशि पर प्रोदभूत व्याज सहित तुरन्त शोधय और संदेय हो जाएगी। सरकार उक्त परादेय की राशि को "भू-राजस्व का वकाया" के रूप में वसूल करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने पहले लिखे दिन और तारीख को इस पर अपने हास्ताक्षर कर दिये हैं।

उक्त श्री,

ने

हस्ताक्षर (नाम और पद)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से
(अधिकारी के हस्ताक्षर और पद नाम)

1.
2.

(साक्षी के हस्ताक्षर)

उधार लेने वाले का नाम और पद नाम
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

प्ररूप-II

मोटर यान अग्रिम के लिए बन्धक-पत्र का प्ररूप
(नियम 8 देखें)

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, समनुदेशित और विधिक प्रतिनिधि भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "हिमाचल प्रदेश सरकार" कहा गया है जिसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी) के बीच आज तारीख.....को किया गया है ।

उधार लेने वाले ने.....रुपये (केवल.....रुपये) के लिए आवेदन किया है और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वेतन और भत्ते अधिनियम, 1971 के अधीन बनाए गए हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मोटर कार और भवन निर्माण अग्रिम नियम, 2001 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 और 4 के अनुसार मोटर कार खरीदने के लिए.....रुपये का अग्रिम प्रदान किया गया है और एक शर्त जिस पर उधार लेने वाले को उक्त अग्रिम प्रदान किया गया है/था, ये है/थी कि उधार लेने वाला उक्त मोटर कार की हिमाचल प्रदेश सरकार के पास उधार लेने वाले को दी गई राशि के लिए प्रतिभूति रूप में आडमान करेगा और उधार लेने वाले ने यथापूर्वोक्त ऐसी अग्रिम राशि के पूर्ण या अंशतः भाग से मोटर खरीद ली है जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसूचित में निर्दिष्ट है,—

अब यह करार इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसार में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए (उधार लेने वाला) हिमाचल प्रदेश सरकार कोरुपये (.....रुपये) की पूर्वोक्त राशि या उसके बचे अवशेष को इस विलेख की तारीख तक.....रुपये (.....रुपये) की राशि के समान संदाय द्वारा प्रत्येक मास के प्रथम दिन को देगा और ..

तत्समय देय शेष राशि पर ब्याज संदत्त करेगा और बकाया संगणना उक्त नियम के अनुसार करेगा और उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसा संदाय.....द्वारा उसके वेतन से उक्त नियमों में उपबन्धित रीति में विधान सभा सदस्य के रूप में संदेय वेतन या भत्तों या पेंशन से या अन्यथा मासिक कटौतियों द्वारा वसूल किया जा सकेगा और उक्त करार के अनुसरण में उधार लेने वाला आगे हिमाचल प्रदेश सरकार को उक्त अग्रिम और उक्त नियमों द्वारा उस पर अपेक्षित ब्याज सहित प्रतिभू के रूप में मोटर को समनु-देशित और अन्तरित करता है जिसका विवरण नीचे लिखी अनुसूची में दिया गया है ; और

उधार लेने वाला यह करार करता है और घोषणा करता है कि उसमें उक्त मोटर कार की पूर्ण क्रय कीमत संदत्त कर दी है और वह अब उसकी आत्ययित सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और उक्त अग्रिम के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार को देय धन का बकाया जितने समय तक रहता है वह उस तक उक्त मोटर कार को न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा या न उस सम्पत्ति में या कब्जे को विलग करेगा ;

सर्वदा यह करार और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन या ब्याज की कोई उक्त किस्तें उसके देय होने से दस दिन के भीतर उक्त रीति में संदत्त या वसूल नहीं की जाएगी या उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती

है या मोटर कार को विक्रय करता है या गिरबी रखता है या उसे कब्जे से अलग करता है या दिवालिया हो जाता है या उसके किसी ऋणी से समझौता या अन्य व्यवस्था करता है या उधार लेने वाले के विरुद्ध किसी डिक्री का विनिश्चय के निष्पादन में कार्यवाही करता है, तब उक्त रूप में संगणित व्याज सहित समस्त उक्त मूलधन देय और असंदत्त हो, तुरन्त मंदेय होगा।

यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इसमें पूर्ण वर्णित किसी घटना के घटित होने पर उक्त मोटर कार का अभिग्रहण कर सकेगी और उसे हिलाए या बिना हिलाए अपने कब्जे में रख सकेगी या उक्त मोटर कार को लोक नीलामी द्वारा या निजी संविदा द्वारा विक्रय कर सकेगी और विक्रय राशि में से असंदत्त और यथा पूर्वोक्त संगणित देय व्याज सहित शेष अग्रिम और उचित रूप से उपगत सभी लागतों, प्रभारों, व्ययों और इसके अधीन उसके अधिकार को बनाए रखने, अभिरक्षा करने, और उगाहने के लिए किए गए या उपयुक्त रूप में उपगत संदाए रखेगी और अतिशेष, यदि कोई हो, उधार लेने वाले, उसके निष्पादक प्रशासक या वैयक्तिक प्रतिनिधि को संदत्त करेगी :

परन्तु यह और भी कि पूर्वोक्त कब्जा लेने वाली या उक्त मोटर कार को विक्रय करने की शक्ति उधार लेने वाले या उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध उक्त उपशेष बकाया का देय और व्याज या मोटर कार को बेचे जाने की दशा में, राशि जिसके द्वारा शुद्ध विक्रय आगम देय राशि से कम पड़ते हों, के बारे में मुकद्दमा चलाने के हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी,

उधार लेने वाला आगे यह करार करता है कि जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई धन शोध्य और बकाया रहता है उधार लेने वाला उक्त मोटर कार को अग्नि, चोरी, दुर्घटना द्वारा हानि के विरुद्ध किसी सामान्य बीमा कारबार करने वाली किसी बीमा कम्पनी/नियम के साथ बीमा करेगा और संपरीक्षा अधिकारी के समाधान के लिए यह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि सामान्य बीमा कारबार करने वाली बीमा कम्पनी/निगम में जिसके साथ उक्त मोटर कार बीमाकृत है न संचना प्राप्त कर ली है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पालिसी में हितबद्ध है ;

उधार लेने वाला आगे यह करार भी करता है कि उक्त मोटर कार को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं होने देगा या उस मात्रा से अधिक क्षय नहीं होने देगा जो उसके युक्तियुक्त टूटफूट से होती हो और आगे यह कि उक्त मोटर कार को किसी हानि या दुर्घटना घटने की दशा में उधार लेने वाला तुरन्त उसकी मरम्मत करेगा और नुकसान को पूरा करेगा।

अनुसूची

मोटर कार का वर्णन
 बनाने वाले का नाम
 विवरण
 सिलण्डरों की संख्या
 इंजन संख्या
 चेसिस संख्या
 लागत कीमत

इसके साक्ष्य स्वरूप उक्त

(उधार लेने वाले का नाम) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से उक्त श्री ने उपर लिखित दिन और वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त उधार लेने वाले

1. (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
 2. (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
- की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से श्री

1. (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

- 2 (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।
(अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)

प्ररूप-III

बीमा पालिसी में जोड़े जाने वाले खण्ड के प्ररूप
(नियम-II देखें)

यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री (मोटर कार का स्वामी जिसे इसमें इसके पश्चात् इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) के पास मोटर कार खरीदने के लिए प्रतिभूत के रूप में आड़मान कर दिया है और यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार ऐसे धन में भी हितबद्ध है जो यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री इस पालिसी के अधीन बीमाकृत (को उक्त मोटर कार की हानियां उसको हुए नुकसान की बाबत) जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति, मुरम्मत, या पूर्णकरण या प्रतिस्थापना द्वारा नहीं की गई संदेय होगा और ऐसा धन सरकार को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह मोटर कार की बन्धकदार है और उनकी रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत निगम ने पूरा और अन्तिम भुगतान कर दिया है ।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है उसके सिवाये इसकी किसी भी बात से बीमाकृत के या कम्पनी के, इस पालिसी के अधीन या सम्बन्ध में अधिकार या दायित्व का अथवा इस पालिसी के किसी निबन्धन, उपबन्ध या शर्त का न तो उपान्तरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा ।

प्ररूप-IV

(नियम 12 देखिए)

भवन निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि के लिए आवेदन का प्ररूप

- विधान सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का नाम स्पष्ट अक्षरों में
 - अपेक्षित अग्रिम की धनराशि यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या
(I) भवन निर्माण के लिए अपेक्षित, अथवा
(II) बने हुए भवन के लिए अपेक्षित है
 - स्थान, जहां पर भवन बनाया जाना है, और यदि ऋण बने हुए भवन की खरीद के लिए अपेक्षित हो तो भवन की लागत के उचित होने के सम्बन्ध में वास्तुविद अर्थात् आर्किटेक्ट का प्रमाण-पत्र साथ लगाया जाए ।
 - किस्तों की संख्या जिनमें अग्रिम धनराशि ली जानी प्रस्तावित है अथवा एक मुश्त में
 - अग्रिम सहित ऋण वापसी के लिए प्रस्तावित किस्तों की संख्या
 - क्या वह प्लॉट जिस पर विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भवन निर्माण का इरादा रखते हैं उनके स्वामित्व और कब्जे में है
 - लाट/जमीन जिस पर आवेदक भवन निर्माण का इरादा रखता है, पर उनके हक का प्रमाणित सबूत
 - समय जिसके अन्दर विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ करेंगे और उसके पूरा होने की अवधि
- प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं बने हुए भवन/प्लॉट जिस पर भवन बनाया जाना है को बंधक रखूंगा तथा बन्धक पत्र निष्पादित और पंजीकृत करवाऊंगा ।

(विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

- तारीख
- संलग्न

प्ररूप-व

(नियम 16 देखिए)

भवन निर्माण अग्रिम राशि के लिए बन्धक का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री जो कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "बन्धक कर्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां सन्दर्भ के अनुकूल है, उनके वारिस, निष्पादक, समनुदेशिनी और विधिक प्रतिनिधि भी है) तथा दूसरे पक्षकार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "बन्धकदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां, सन्दर्भ के अनुकूल है, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिनी भी है) आज तारीख का किया गया है ।

चूंकि एतद्द्वारा स्वत्वान्तरित, हस्तान्तरित और बीमाकृत की जाने वाली भूमि दाय और परिसरों जिन्हें इसमें आगे वर्णित और अभिव्यक्ति किया गया है (इसमें इसके पश्चात् "उक्त दाय" कहा गया है) पर बन्धककर्ता निरन्तुश रूप में अभिग्रहण और कब्जा है अथवा अन्यथा रूप में उनका हकदार सही है ।

और चूंकि बन्धक ने बन्धकदार को अपने निजी प्रयोग के लिए अपना भवन बनाने के लिए नवनिर्मित भवन खरीदने हेतु रुपये की अग्रिम धनराशि के लिए आवेदन पत्र दिया है ;

और चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (मोटरकार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण), नियम 2001, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है और इनके अन्तर्गत जब तक कि सन्दर्भ के अनुकूल है वर्तमान प्रवृत्त नियम, उनका कोई संशोधन या उसमें कोई परिवर्धन भी आता है) बन्धकदार बन्धककर्ता को रुपये की उक्त रकम निम्नलिखित रूप में भुगतान योग्य अग्रिम धनराशि के रूप में देने को सहमत है,

(क) निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए, रुपये

(ख) भवन को छत की सतह तक पूर्ण कर लेने के पश्चात् रुपये

(ग) अथवा एक मुश्त राशि के रूप में, रुपये

यह करार इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में तथा बन्धकदार द्वारा बन्धककर्ता को इसम इससे पूर्व उल्लिखित खर्चों को करने में बन्धककर्ता को सशक्त बनाने के प्रयोजन से इस करार के निष्पादन के पश्चात् या उससे पहले प्रदत्त रुपये

(रुपये) जिसको पावती बन्धककर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है (और ऐसी और धनराशि जो इस करार में आगे उल्लिखित उपबन्धों के अनुसरण में बन्धकदार द्वारा बन्धककर्ता को दी जाएगी) और उस पर उक्त नियमों में निर्धारित रीति से गणित व्याज, जिसकी पुनः अदायगी के लिए बन्धककर्ता एतद्द्वारा प्रसविदा करता है के प्रतिफल के लिए बन्धककर्ता यह करार करता है ।

और यह करार इस बात का भी साक्षी है कि पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए बन्धककर्ता बन्धकदार को इस सारे भूखण्ड को जो बन्धककर्ता के लगभग गव्जे में है तथा जो जिले पंजीकरण जिला के में स्थित है तथा जो उत्तर में के पूर्व में से दक्षिण में से तथा पश्चिम में से परिसीमित है एवं उस पर अब उस बनाये गए रिहायशी मकान अथवा इसके पश्चात् बनाये जाने वाले रिहायशी मकानों के साथ उक्त दाय के सभी अधिकार, सुखाधिकार, अनुलग्न और उक्त भूमि के खण्ड पर इसके पश्चात् खड़े किए गए या बनाये गए मकानों को बन्धकदार और उसकी ओर से पूर्ण प्रयोग के लिए इसमें इसके पश्चात् निहित परन्तुक में दिये गए विमोचन के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए एतद्द्वारा स्वत्वान्तरित, हस्तान्तरित और प्राश्वस्त करता है ।

संव्या यह भी करार दिया जाता है कि यदि और ज्योंही इस करार में उल्लिखित प्रतिभूति पर की गई उक्त अग्रिम धनराशि रुपये (और ऐसी अन्य रकमें जिनका यथा पूर्वोक्त भुगतान किया गया हो) और उक्त नियमों में उपबन्धित या किसी अन्य

रीति से गणित उस पर व्याज यदि वापिस लिया जाता है, तब और ऐसी स्थिति में बन्धकदार बन्धककर्ता को प्रार्थना और लागत पर बन्धककर्ता के प्रयोग और उसकी ओर से प्रयोग अथवा जैसे वह निर्देश दें, उक्त दाय को पुनः स्वत्वांतरित पुनः हस्तांतरित और पुनः आश्वस्त करेगा और इस द्वारा यह करार अथवा घोषित किया जाता है कि यदि बन्धककर्ता इकरार को भंग करता है और यदि उक्त रकम रुपये..... और कोई अन्य रकम जिनका यथापूर्व भुगतान किया जाना हो और उक्त नियमों के अनुसार उस पर प्रमाणित प्रगणित किए गए व्याज के पूरे भुगतान से पहले यदि उनकी मृत्यु हो जाती है या वह अध्यक्ष/उपाध्यक्ष क पद पर नहीं रहते हैं तो इस प्रकार की सभी स्थितियों में बन्धकदार के लिए उपयुक्त समझे, को करने और उसके लिए विधि मान्य होगा कि वह उक्त दाय को या उसके किसी अंश को इकट्ठे या आंशिक रूप से सार्वजनिक या निजी संविदा के द्वारा संविदा को रद्द या निरस्त करने की शक्ति सहित विक्रय और उस द्वारा होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी हुए/पुनः विक्रय कर सके।

तथा वह ऐसे किसी विक्रय जिसे, बन्धकदार उपयुक्त समझे, को करने और उसके लिए आवश्यक सभी कार्यों तथा आश्वासनों को निष्पन्न करने में सक्षम होगा तथा एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बन्धकदार विक्रीत परिसरों या उसके किसी भाग से प्राप्त विक्रय आगम में से क्रेता अथवा क्रेताओं को अचूक रूप में मुक्त करेगा, तथा एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि बन्धकदार पूर्वोक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए विक्रय से प्राप्त धनराशि को न्याय के रूप में रखेगा, उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर उपगत हुए खर्च का भुगतान करेगा, उसके पश्चात् इस करार की प्रतिभूति पर फिलहाल देय रकमों के भुगतान की और उस धनराशि से रकम लगाएगा और तब शेष (यदि कोई हो) बन्धककर्ता को देगा तथा एतद्द्वारा, यह माना जाता है तथा घोषित किया जाता है कि उक्त नियमों को इस करार को अंश समझा और माना जाएगा।

बन्धककर्ता, बन्धकग्राहीता के साथ एतद्द्वारा यह प्रसंविदा करता है कि वह बन्धककर्ता अपनी प्रतिभूति के चालू रहने के दौरान, इस करार और उक्त दाय के सम्बन्ध से पालित और अनुष्ठित किए जाने वाले उक्त नियमों के उपबन्धों और शर्तों का पालन और निष्पादन करेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप बन्धककर्ता ने इस विलेख पर ऊपर लिखी तारीख को अपने हस्ताक्षर किए हैं :-

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त बन्धकदाता के द्वारा हस्ताक्षरित :-

पहला साक्षी.....
पता.....
व्यवसाय.....
दूसरा साक्षी.....
पता.....
व्यवसाय.....

प्रारूप-VI

(नियम 16 देखिए)

भवन निर्माण अग्रिम हेतु प्रतिहस्तांतरण

यह अनुबन्ध विलेख तारीख.....को एक पक्षकार के रूप में राज्यपाल हिमाचल प्रदेश (जिन्हें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) एक पक्ष और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री.....अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा (जिन्हें इसके आगे "बन्धककर्ता कहा गया है) के बीच किया गया यह उस बन्धकपत्र के अनुबन्ध विलेख का अनुपूरक है जो कि तारीख.....को एक पक्षकार के रूप में बन्धककर्ता दूसरे पक्षकार के रूप में राज्यपाल के बीच किया गया था तथा जो पुस्तिका के खण्ड.....पृष्ठ.....से.....पर क्रम में पंजीकृत है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मुख्य अनुबन्ध-विलेख" कहा गया है)।

चूंकि मुख्य विलेख अनुबन्ध विलेख के अधीन समस्त देय राशि अदा कर दी गई है और उक्त विलेख की प्रतिभूति का दायित्व पूर्णतया शोधित है तथा राज्यपाल बन्धककर्ता के निवेदन पर लिखित अनुबन्ध विलेख में अन्तर्विष्ट प्रति हस्तान्तरण, जैसा कि एतद् उपरान्त, समाविष्ट है के लिए सहमत हो गए हैं।

अब यह अनुबन्ध विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त मुख्य-विलेख के अनुसरण में और वचनों के प्रतिफल में राज्यपाल एतद्द्वारा बन्धककर्ता, उसके वारिस निष्पादक तथा समनुदेशिनी को भूमि के उन सभी भागों को में स्थित है व उत्तर में से दक्षिण में से पूर्व में से

तथा पश्चिम में लगभग तक परिसीमित है तथा जिसमें उन परिसरों से अन्यथा सामूहिक रूप से उस पर बने निवास, स्थान वाह्य कार्यालय, अश्वशाला, पाकशाला आदि सम्मिलित हैं तथा जो मुख्य अनुबन्ध विलेख में अन्तर्विष्ट या जिनका एतद्द्वारा प्रगोपित होना अभिव्यक्त है अथवा जो कि अब मुख्य अनुबन्ध विलेख के कारण अथवा इसके विमोचन के अध्याधीन किसी भी प्रकार राज्यपाल में निहित उनके अधिकारों, सुविधाओं तथा अनुलग्नकों, जैसा कि मुख्य अनुबन्ध विलेख में अभिव्यक्त है तथा मुख्य अनुबन्ध विलेख के कारण उसी परिसर में से अथवा पर राज्यपाल के सभी सम्पदा अधिकार, स्वत्वाधिकार, हित, सम्पत्ति, प्रभार तथा मांगे जो भी कोई होता उन परिसरों जो एतद्द्वारा इससे पूर्व बन्धककर्ता, उसके वारिसों, निष्पादक, प्रबन्धक तथा उसके प्रयोग के लिए स्वीकृत, नियत तथा प्रतिहस्तांतरित है को रखने अथवा बनाये रखने के लिए तथा मुख्य अनुबन्ध विलेख द्वारा रक्षित होने के लिए उस सारे धन से अथवा उपरोक्त राशि अथवा उसके किसी भी अंश अथवा परिसर व मुख्य अनुबन्ध विलेख से सम्बद्ध सभी कार्यों वादों, लेखों, दावों, मांगों से सदा के लिए मुक्त करता है,

प्रमंविदा करते हैं तथा अधिहस्ताकित करते हैं कि राज्यपाल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है अथवा इसके लिए जानबूझ कर ममनुजा नहीं की है अथवा इसके लिए वह एक पक्ष अथवा सहभागी नहीं रहे हैं जिसके द्वारा उपरोक्त परिसर अथवा उसके किसी भी भाग के लिए उन पर महाभियोग लाया जाएगा लाया जा सकता है। स्वत्वधिकार सम्पदा अथवा इसके अन्यथा जो भी हो में परिबन्धन अथवा रुकावट लाए जा सके। इसके साक्ष्य स्वरूप इससे सम्बन्ध पक्षकारों इस पर ऊपरलिखित दिन और वर्ष को मोहर सहित अपने हस्ताक्षर किए हैं।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से
हस्ताक्षरित, मोहरबन्द तथा प्रदत्त किया

1.
2.

की उपस्थिति में :

[Authoritative English text of the department notification No. GAD-C (PA)-4-1/95-III-dated 11-4-2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th April, 2001

No. GAD-C-(PA) 4-1/95-III.—In exercise of the powers conferred by section 13 read with sections 7 and 7-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speakers Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to regulate advance for Motor Car and House Building of the Speaker and Deputy Speaker, namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Definition.*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—
- (a) "Act" means the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 ;
 - (b) "Speaker/Deputy Speaker" means the Speaker/Deputy Speaker of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh ;
 - (c) "Audit Officer" means the Accountant General, Himachal Pradesh ;
 - (d) "Form" means Form appended to these rules ;
 - (e) "Sanctioning Authority" means the Governor of Himachal Pradesh ; and
 - (f) Terms and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

MOTOR CAR ADVANCE

3. *Advance when admissible.*—The Speaker or Deputy Speaker as the case may be, may be paid an advance for the purchase of a motor car in order that he may be discharge conveniently able to discharge conveniently and efficiently the duties of his office subject to the conditions hereinafter specified.

4. *Maximum amount of advance.*—The maximum amount which may be advanced to the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, for the purchase of a motor car shall not exceed rupees ten lacs or the actual price of the motor car which is intended to be purchase, whichever is less :

Provided that in case the Speaker or the Deputy Speaker as the case may be has taken the house building advance under rule 13 of the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000 or under rule 13 or these rules, or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Advance of Loan for House Building) Rules, 1979, then the total amount of the motor car advance together with the house building advance already availed of by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, shall not exceed the limit of ten lacs rupees :

Provided further that where Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, has taken the motor car advance in his capacity as the Minister or the Member of Legislative Assembly as the case may be, the total amount of motor car advance together with the motor car advance already given to him shall not exceed the limit of ten lacs rupees.

5. *Recovery of advance.*—(1) Recovery of the advance granted under rule 4 together with interest thereon, shall be made in 180 equal monthly instalments. The Government may order recovery to be made in a smaller number of instalments keeping in view the remaining period of term of office or if the Speaker/Deputy Speaker himself so desires. The deduction shall commence with the first issue of salary after the advance is drawn.

(2) Simple interest at the rate of 5% per annum shall be charged in respect of the loans sanctioned on or after 3-12-1993 :

Provided that the rate of interest fixed on the loans sanctioned prior to 3-12-1993 shall hold good for the entire duration of the advance.

(3) If the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, ceases to be Speaker or Deputy Speaker, for any reason, before the advance is fully repaid, but continues to be a Member of Legislative Assembly, the monthly instalments shall be recovered by the Vidhan Sabha Secretariat out of the various allowances admissible to him as a Member of the Legislative Assembly.

(4) If Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, ceases to be the Member of the Legislative Assembly, before the advance is fully repaid, but he is entitled to draw pension, the recovery shall be made by the Vidhan Sabha Secretariat out of the pension payable to him and the balance amount of the monthly instalments shall be deposited by him regularly in the Government Treasury and in token of proof of such payment, he shall submit a copy of the challan to the Government regularly.

(5) In case he ceases to be Member of Legislative Assembly and is also not entitled to draw the pension, the monthly instalments, together with interest accrued thereon, shall be deposited

by him regularly in Government Treasury and he shall submit a copy of the Challan to the Government in token of proof of having deposited the amount.

(6) In the event of death before the recovery of advance alongwith interest thereon, the legal representative(s) of Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, shall deposit the balance of the amount of the loan and interest accrued thereon in lump-sum in the Government Treasury and submit a copy of the Challan to the Government in token of proof of having deposited the whole amount.

(7) If the Speaker or Deputy Speaker, or his legal representative(s), as the case may be default in regular payment of instalments either of the principal or interest thereon, or if becomes insolvent(s) or fail(s) to observe or perform the terms and conditions of the loan, then in such a case the whole of the principal amount of the loan or such thereof as shall then remain due and unpaid, shall become payable forthwith in lump-sum to the Government with interest thereon at the rate specified in sub-rule (2).

The Government shall be at liberty to recover the said outstanding amount as "Arrears Land Revenue". The recovery to be effected by Vidhan Sabha Secretariat, as envisaged in the above conditions, will be regulated under the Himachal Pradesh Legislative Assembly members (Advance to Loan for purchase of Motor Car) Rules, 1979 as in force from time to time.

Explanation.—The amount of the advance to be recovered monthly shall be fixed in whole rupees except in the case of last instalment when the remaining balance including any fraction of a rupee shall be recovered.

6. *Sale of motor car.*—(1) Except when the Speaker or Deputy Speaker as the case may be, relinquishes his office the previous sanction of the Government shall be obtained for the sale by the Speaker or Deputy Speaker as the case may be, of the motor car purchased with the aid of an advance, if such advance together with interest accrued thereon has not been fully repaid.

(2) In all cases where a motor car is sold before the advance with interest thereon has been fully repaid, the sale proceeds must be applied, so far as may be necessary towards the payment of such outstanding balance:

Provided that when the motor car is sold only in order that another motor car may be purchased, the Government may permit the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, to apply the sale proceeds towards such purchase, subject to the following conditions, namely:—

- (a) the amount outstanding shall not be permitted to exceed the cost of the new car ;
- (b) the amount outstanding shall continue to be repaid at the rate previously fixed ; and
- (c) the new car shall be mortgaged to the Government and also insured.

7. *Period within which negotiations for purchase of car may be completed.*—The Speaker or Deputy Speaker, as the case may be who draws an advance for the purchase of a motor car, shall complete negotiations for the purchase of and make final payment for the motor car within one month of the date on which he draws the advance, failing such completion and payment, the full amount of the advance drawn, with interest thereon for one month, shall be refunded to the Government. The period of one month for completion of the deal may, however, be extended by the Government in individual cases. An advance will not be admissible when a motor car has already been purchased and paid for in full. In a case in which payment has been made in part, the amount of advance will be limited to the balance to be paid as certified by the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

8. *Execution of agreement.*—At the time of drawing the advance the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, shall execute an agreement in Form-I and on completing the purchase, he shall further execute a mortgage bond in Form-II hypothecating the motor car to the Government as security for the advance. The cost price of the motor car shall be entered in the Schedule of specifications attached to the mortgage bond.

9. *Certificate to the Audit Officer.*—When an advance is drawn, the sanctioning authority shall furnish to the Audit Officer a certificate that the agreement in Form-II has been signed by the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, drawing the advance and that it has been found to be in order. The sanctioning authority shall see that the motor car is purchased within

one month from the date on which the advance is drawn or such period as may have been specifically allowed in individual cases by the Government for completion of the deal under rule 7 and shall submit every mortgage bond promptly to the Audit Officer for examination before final record.

10. *Safe custody and cancellation of mortgage bond.*—The mortgage bond shall be kept in the safe custody of the sanctioning authority. When the advance together with the interest thereon has been fully repaid, the bond shall be returned to the Speaker or Deputy Speaker as the case may be, duly cancelled after obtaining a certificate from the Audit Officer as to the complete repayment of the advance and interest.

11. *Insurance of the Motor Car.*—The motor car purchased with the advance shall be insured against full loss by fire, theft or accident with the any Insurance Company Corporation transacting any General Insurance Business. The Insurance policy shall contain a clause as in Form-III by which the Corporation agrees to pay to Government instead of the owner, any sum payable in respect of loss or damage to the motor car which is not made good by repair, re-insatement or replacement such insurance should be effected within one month of the date of the purchase.

HOUSE BUILDING ADVANCE

12. *Advance when admissible.*—On an application made in Form-IV by the Speaker or the Deputy Speaker as the case may be, may be paid a repayable advance, for the construction of his own house or for the purchase of a built up house with a view to have a reasonable standard of living.

13. *Maximum amount of Advance.*—The maximum amount which may be advanced to the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be for the construction of a house or for the purchase of built up house shall not exceed ten lacs rupees or the actual price or cost of the construction of house, whichever is less :

Provided that in case the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, has taken the motor car advance under rule 4 of these rules or under rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers Advance for Motor Car and House Building Rules, 2000 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Advance of Loan for purchase of Motor Car) Rules, 1979, then the total amount of house building advance together with the motor car advance already availed of by the Speaker or the Deputy Speaker as the case may be, shall not exceed the limit of ten lacs rupees :

Provided further that where Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, has taken the house building advance in his capacity as the Minister or the Member of Legislative Assembly as the case may be, the total amount of house building advance together with the house building advance already given to him shall not exceed the limit of ten lacs rupees.

14. *Mode of payment.*—The amount of advance admissible under these rules shall be paid in the following manner :—

(1) For the construction of his own house:—

- (a) first instalment equal to 50 % of the advance sanctioned for starting the construction :
- (b) second and final instalment of the remaining 50% of the total advance after the house has been completed upto the roof level.

(2) For the purchase of the new built-up house in lump-sum.

Note.—A certificate which must be furnished by the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, certifying that the amount drawn has been utilised by him for the purpose which it was advanced to him will be sufficient proof of the amount having been actually utilised by him for the aforesaid purpose.

15. *Recovery of advance.*—(1) Recovery of the advance granted under rule 13 together with interest thereon shall be made in 180 equal monthly instalments. The Government may order recovery to be made in a small number of instalments, keeping in view the remaining period of term of office or if the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, himself so desires. The deduction shall commence with the first issue of salary after the first instalment of/or lump sum advance is drawn.

(2) Simple interest at the rate of 5% per annum shall be charged in respect of the loans sanctioned on or after 3-12-1993 :

Provided that the rate of interest fixed on the loans sanctioned prior to 3-12-1993 shall hold good for the entire duration of the advance.

(3) If the Speaker or Deputy Speaker as the case may be, ceases to be a speaker or Deputy Speaker, as the case may be, for any reason, before the advance is fully repaid, but continues to be Member of Legislative Assembly, the monthly instalments shall be recovered by the Vidhan Sabha Secretariat out of the various allowances admissible to him as Member of Legislative Assembly.

(4) If Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, also ceases to be the Member of Legislative Assembly, before the advance is fully repaid, but he is entitled to draw pension, the recovery shall be made by the Vidhan Sabha Secretariat out of the pension payable to him and the balance amount of the monthly instalments shall be deposited by him regularly in the Government Treasury and in token of proof of such payment, he shall submit a copy of the challan to the Government regularly.

(5) In case he ceases to be a Member of Legislative Assembly and is also not entitled to draw the pension, the monthly instalments, together with interest accrued thereon, shall be deposited by him regularly in Government Treasury and he shall submit a copy of the challan to the Government in token of proof of having deposited the amount.

(6) In the event of death before the recovery of advance along with interest thereon, the legal representative(s) of the Speaker or Deputy Speaker shall regularly deposit the monthly instalments in the Government Treasury and submit the copy of the challan to the Government, every month in token of proof of having deposited the amount.

(7) If the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, or his legal representatives, as the case may be, makes default in regular payment of instalments either of the principal or interest thereon, or if becomes insolvent or fails to observe or perform the terms and conditions of the loan, then in such a case the whole of the principal amount of the loan or so much thereof as shall then remain due and unpaid shall become payable forthwith in a lump sum to the Government with interest thereon at the rate specified in sub-rule (2). The Government shall be at liberty to recover the said outstanding amount as 'Arrears of Land Revenue'.

Explanation.—The amount of the advance to be recovered monthly shall be fixed in whole rupees except in the case of last instalment when the remaining balance including any fraction of a rupee shall be recovered.

16. *Liability to execute mortgage deed securing the payment of the loan.*—In order to secure Government from loss consequent on the demise of Speaker or the Deputy Speaker, as the case

may be, for ceasing to be the Speaker or Deputy Speaker, before full repayment of the advance and the interest accrued thereon, the house so built or purchased, together with the land on which it stands upon, shall be mortgaged to the Himachal Pradesh Government in Form-V appended to these rules which shall be executed before the payment of the first instalment or of lump sum, as the case may be, as made, and on full payment of the amount which accrued to be due, the mortgage shall be released after the execution of the reconveyance deed in Form VI appended to these rules. On the execution of the mortgage deed, the sanctioning authority shall satisfy itself as to the correctness of the applicant's title to the land upon which the house stands or is proposed to be built.

17. *Liability to keep premises in good repairs and insure the premises against fire risks, etc.*—The Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, shall maintain the house in good repair, at his own cost and shall also keep it free from all encumbrances. He shall also have it insured for a sum not less than the amount of advance sanctioned, against fire, flood etc. etc. and furnish an annual certificate to this effect.

18. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971 and the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loans for House Building) Rules, 1981 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.

FORM-I

FORM OF AGREEMENT TO BE EXECUTED AT THE TIME OF DRAWING AN ADVANCE FOR THE PURCHASE OF MOTOR CAR

(See rule 8)

An agreement made this.....day of.....between Shri..... Speaker/Deputy Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (hereinafter called the "Borrower which expression shall include his heirs, administrators, executors, legal representatives and assigns) of the one part and the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter called "the Government of Himachal Pradesh" which expression shall include his successors and assigns) of the other part.

Whereas the Borrower has under the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001 applied to the Government for a loan of Rs.....(Rupees.....only) for the purchase of a Motor car and the Government has agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained.

2. Now it is hereby agreed between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs.....(Rupees.....only) paid by the Government of Himachal Pradesh to the Borrower (the receipt of which the borrower hereby acknowledges) the Borrower hereby agrees with the Government.—

(1) to pay the Government that said amount with interest calculated according to the said rules bymonthly deductions from his salary or allowances/pension

payable as Member Legislative Assembly (as much as could be recovered and the rest to be deposited in cash by him in Government Treasury) as provided for by the said rules and hereby authorises the Government to make such deductions and in case the Borrower is not entitled to draw the pension, the monthly instalments together with interest accrued thereon, shall be deposited by him regularly in Government treasury and he shall submit a copy of the challan to the Government in token of having deposited the amount as provided for by the said rules ;

- (2) within one month from the date of these presents to expend the full amount of the said loan in the purchase of a motor car or if the actual price paid is less than the loan, to repay the difference to the Government forth with ; and
- (3) to execute a document hypothecating the said motor car to the Government as security for the amount lent to the Borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said rules.

And it is hereby lastly agreed and declared that if the motor car is not purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of these presents or within the extended period or if the Borrower within that period become insolvent or relinquishes his office or otherwise ceases to be Speaker/Deputy Speaker, or dies, the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall immediately become due and payable. (The Government shall be at liberty to recover the said outstanding amount as "Arrears of Land Revenue").

In witness whereof the Borrower has hereunto set his hand the day and year first before written.

Signed by the said Shri.....

In the presence of.....

Signed by (name and designation).....

For and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of.—

(Signature and designation of the Officer).

1.....

2.....

(Signature of witnesses)

Name and designation of the Borrower.

FORM-II

FORM OF MORTGAGE BOND FOR MOTOR VEHICLE ADVANCE

(See rule 8)

This indenture made this.....day of.....between.....
(hereinafter called the "Borrower" which expression shall include his heirs administrators executors, assigns and legal representatives) of the one part and the Governor of Himachal Pradesh (hereinafter called the "Government of Himachal Pradesh" which expression shall include his successors and assigns) of the other part :

Whereas the Borrower has applied for and has been granted an advance of Rs. (Rupees. only) to purchase a motor car in the terms of rules 3 and 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car and House Building) Rules, 2001 made under the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (hereinafter referred to as "the said Rules") and whereas one of the conditions upon the said advance has been/was granted to the Borrower is/was that the Borrower will/would hypothecate the said motor car to the Government of Himachal Pradesh as security for the amount lent to the Borrower and whereas the Borrower has purchased with whole or partly with the amount so advanced as aforesaid the motor car particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written :

Now this indenture witnesseth that in pursuance of the said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth hereby covenant to pay to the Government of Himachal Pradesh the sum of Rs. (Rupees. only) aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by equal payment of Rs. (Rupees. only) each on the first day of every month and will pay interest on the sum for the time being remaining due and owing calculated according to the said rules and the Borrower doth agree that such payments may be recovered by. monthly deductions from his salary (allowances or pension payable as Member Legislative Assembly or otherwise) in the manner provided by the said rules, and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth hereby assign and transfer unto the Government of Himachal Pradesh the motor car the particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said rules ;

And the Borrower doth hereby agree and declare that he has paid in full the purchase price of the said motor car and that the same is his absolute property and that he has not pledged and so long as any money remains payable to the Government of Himachal Pradesh in respect of the said advance, will not sell, pledge or part with the property in or possession of the said motor car :

Provided always and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of principal or interest shall not be paid or recovered in the manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said motor car or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgement against the Borrower, the whole of the said principal sum which shall then be remaining due and unpaid together with interest thereon calculated as aforesaid shall forthwith become payable ;

And it is hereby agreed and declared that the Government of Himachal Pradesh may on the happening of any of the events herein before mentioned seize and take possession of the said motor car and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said motor car either by public auction or private contract and may, out of the sale money retain the balance of the said advance then remaining unpaid and any interest due thereon calculated as aforesaid and all costs, charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realising his rights hereunder and shall pay over the surplus, if any, to the Borrower, his executors, administrator or personal representatives :

Provided further that the aforesaid power of taking possession or selling of the said motor car shall not prejudice the right of the Government of Himachal Pradesh to sue the Borrower or his legal representatives for the said balance remaining due and interest or in the case of the motor car being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing ;

And the Borrower hereby further agrees that so long as any money are remaining due and owing to the Government of Himachal Pradesh, he the Borrower will ensure and keep insured

the said motor car against loss or damage by fire, theft or accident with any Insurance Company/ Corporation transacting any General Insurance Business and will produce evidence to the satisfaction of the Audit Officer that the Insurance Company/Corporation transacting any General Insurance Business with whom the said motor car is insured have received notice that the Government of Himachal Pradesh is interested in the policy :

And the Borrower hereby further agrees that he will not permit or suffer the said motor car to be destroyed or injured or to deteriorate in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof and further that in the event of any damage or accident happening to the said motor car the Borrower will forth with have the same repaired and made good.

THE SCHEDULE

Description of motor car.....
 Maker's name.....
 Description.....
 Number of cylinders.....
 Engine number.....
 Chassis number.....
 Cost price.....

In witness whereof the said.....(Borrower's name) and said Shri.....
 for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh have hereunto set their respective hands the day and year first above written.

Signed by the said in the presence of :

1.

2.

(Signature of witnesses)

(Signature and designation of the Borrower)

Signed by Name and designation)

.....

for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh in the presence of:

1.

2.

(Signature of witnesses)

(Signature and designation of the Officer)

FORM-III

FORM OF THE CLAUSE TO BE INSERTED IN INSURANCE POLICIES

(See rule 11)

It is hereby declared and agreed that Shri.....(the owner of the motor car herein after referred to as the insured in the Schedule of this policy) has hypothecated the car to the Governor

of Himachal Pradesh (hereinafter called the "Government") as security for advance for the purchase of motor car and it is further declared and agreed that the said Government is interested in moneys which but for this endorsement would be payable to the said Shri..... (the insured under this policy) in respect of the loss or damage to the said motor car (which loss or damage is not made good by repair, reinstatement or replacement) and such moneys shall be paid to the Government as long as they are the mortgagees of the motor car and their receipt shall be full and final discharge to the company in respect of such loss or damage.

2. Save as by this endorsement expressly agreed, nothing shall modify or effect the rights or liabilities of the insured or the company respectively under or in connection with this policy or any term, provision or condition thereof.

FORM-IV

(See rule 12)

APPLICATION FORM FOR HOUSE BUILDING ADVANCE

1. Name of the Speaker or the Deputy Speaker (in block letters)
2. Amount of advance required indicating whether:—
 - (i) required for construction of a house ; or
 - (ii) for the purchase of a built-up house.
3. Place where the house is proposed to be constructed and if the loan is required for the purchase of a built-up house, a certificate from the architect with regard to the reasonableness of the cost of the house be attached.
4. Number of instalments in which the advance is proposed to be drawn or in lump-sum.
5. Number of instalments including the advance is proposed to be repaid.
6. Whether the plot on which the Speaker or the Deputy Speaker intends to construct the house is in his proprietorship and possession.
7. Authentic proof of his title to the plot/land on which the applicant intends to construct the house.
8. Time by which the Speaker or the Deputy Speaker propose to undertake the construction of the house and its completion.

Certified that the above information is correct to the best of my knowledge and that I undertake to mortgage the built-up house/the plot on which the house is to be constructed and execute and register a mortgage deed.

Dated

(Signature of the Speaker/Deputy Speaker).

Encl :

FORM-V

(See rule 16)

FORM OF MORTGAGE FOR HOUSE BUILDING ADVANCE

THIS INDENTURE is made the.....day of.....between Shri.....
 Speaker/Deputy Speaker of the Himachal Pradesh (hereinafter referred to as "the mortgagor"
 which term shall where the context so admits include his heirs, executors, administrators assigns,
 and legal representative (s) of the one part and the GOVERNOR of the Himachal Pradesh (here
 inafter referred to as "the mortgagee" which term shall where the context so admits include his
 successors and assigns) of the other part :

WHEREAS the mortgagor is absolutely seized and possess of or otherwise well entitled to
 the land, hereditament and premises here inafter described and expressed to be hereby conveyed
 transferred and assured hereinafter referred to as "the said hereditaments";

AND WHEREAS the mortgagor has applied to the mortgagee for an advance of the sum of
 Rs. for the purpose of enabling him to construct his own house/purchase a new built-up house
 for his own personal use :

AND WHEREAS under the provisions contained in the Himachal Pradesh Legislative Assem-
 bly Speaker's and the Deputy Speaker's (Advance for Motor Car and House Building) Rules,
 2001 (hereinafter referred to as "the said rules" which expression shall where the context so admits
 include any amendment thereof or addition thereto for the time being in force) the mortgagee has
 agreed to advance to the mortgagor the said sum of Rs.....payable as follows :

- (a) Rs.....for starting construction
- (b) Rs.....after the house has been completed upto roof level
- (c) or in lump sum

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and in
 consideration of the sum of Rs.....(Rupees.....only) paid on or before the
 execution of these presents to be mortgagor by the mortgagee (the receipt whereof the mortgagor,
 doth hereby acknowledge for the purpose of enabling the mortgagor to defray the hereinbefore
 recited expenses the mortgagor hereby covenants with the mortgagee to repay to the mortgagee
 the said sum of Rs.....(Rupees.....only) (and such further sum as shall hereafter be
 paid by him to the mortgagor pursuant to the hereinafter recited agreement in that behalf) and
 interest thereon calculated in the manner set forth in the said rules ;

AND THIS INDENTURE ALSO WITNESSETH that for the consideration aforesaid the
 mortgagor doth hereby convey, transfer and assure unto the mortgagee all that piece of land
 situated in the.....district of.....registration District of.....
 sub-registration District of.....containing.....more or less now in the
 occupation of the mortgagor and bounded on the East by.....on the North by.....
 on the South by.....and on the West by.....together with the dwelling house
 now erected or hereafter to be erected on the said piece of land together with all rights easements
 and appurtenances to the said hereditaments and buildings hereafter erected and built on the said
 piece of land unto and to the use of the mortgagee absolutely subject to the proviso for redemption
 contained :

PROVIDED ALWAYS if and as soon as the said advance of Rupees.....(and of such
 further sums as may have been paid as aforesaid) made upon the security of these presents shall
 have been repaid and interest thereon calculated according to the said rules as in the said
 rules mentioned or by any other means whatsoever then and in such case the mortgagee will

upon the request and at the cost of the mortgagor reconvey, retransfer or ressure the said hereditaments until and to the use of the mortgagor or as he may direct and it is hereby agreed and declared that it there shall be any breach by the mortgagor of the covenants on his part herein contained or if he shall die or ceases or be a Speaker/Deputy Speaker before the said sum of Rupees.....(and any further sum as may have been paid as aforesaid) and interest thereon calculated according to the said rules shall have been fully paid off then and in any of such cases it shall be lawful for the mortgagee to sell the said hereditaments or any part thereof either together or in partial and either by public auction or by private contract with power to nullify or rescind any contract for sale and to resell without being responsible for any loss which may be occasioned thereby ;

AND to do and execute all such acts and assurances for effectuating any such sale as the mortgagee shall think fit AND it is hereby declared that the receipt of the mortgagee for the purchase money of the premises sold or any part thereof shall effectually discharge the purchaser or purchasers therefrom AND it is hereby declared that the mortgagee shall hold the moneys to arise from any sale in pursuance of the aforesaid power UPON TRUST in the first place thereout to pay all expenses incurred on such sale and in the next place to apply such moneys in or towards satisfactions of the moneys for the time being owing on the security of these presents and then to pay the surplus (if any) to the mortgagor AND it is hereby agreed and declared that the said rules shall be deemed and taken to be part of these presents.

The mortgagor hereby convents with the mortgagee that he, the mortgagor, will during the the continuance of his security observe and perform all the provisions and conditions of the said rules on his part to be observed and performed in respects of these presents and the said hereditaments

IN WITNESS whereof the mortgagor, hath hereunto set his hand the day and year first above written.

Signed by the said (Mortgagor)

In the presence of :

1st witness :

Address

Occupation

2nd witness :

Address

Occupation

FORM-VI

(See rule 16)

RECONVEYANCE FOR HOUSE BUILDING ADVANCES

THIS INDENTURE is made the.....day of.....BETWEEN THE GOVERNOR OF HIMACHAL PRADESH (hereinafter called the Government) of the one part and Shri.....Speaker/Deputy Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly

(hereinafter called "the mortgagor") of the other part is supplemental to an Indenture of mortgage, dated the day of and made BETWEEN THE MORTGAGOR OF THE one part and the Governor of the other part and registered at in Block Volume pages to and as No for hereinafter called the PRINCIPAL INDENTURE.

WHEREAS all moneys due and owing on the security of the PRINCIPAL INDENTURE have been fully paid and satisfied and the Governor has accordingly at the request of the mortgagor agreed to execute such reconveyance of the mortgaged premises in the within written INDENTURE comprised as is hereinafter contained ;

NOW THIS INDENTURE WITNESSTH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the premises, the Governor doth hereby grant, assign and reconvey upto the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns ALL THAT piece of land situated in the containing more or less bounded on the North by on the South by on the East by on the West by to therewith the dwelling house and out offices, stables, cook-rooms and out buildings thereon AND ALL and singular other than permises in the PRINCIPAL INDENTURE comprised or expressed to be thereby assured or which now are by any means vested in the Governor subject to redemption under or by virtue of the PRINCIPAL INDENTURE with their rights, easements and appurtenances as in the PRINCIPAL INDENTURE expressed and all the estates right, title, interest property clean and demand whatsoever of the Governor into out of or upon the same premises by virtue of the PRINCIPAL INDENTURE to have and to hold the premises hereinbefore expressed to be hereby granted, assigned and reconveyed upon and to the use of the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns forever freed and discharged from all moneys intended to be secured by the PRINCIPAL INDENTURE and from all actions, suits, accounts, claims and demands for, or in respect of the said monies or any part thereof or PRINCIPAL INDENTURE of anything relating to the premises :

AND the Governor hereby covenants with the mortgagor, his heirs, executors, administrators and assigns that the Governor has not done or knowingly suffered or been party or privy to anything whereby the said premises or any part thereof, are, is or can be impeached, encumbered or affected in title, estate or otherwise whatsoever IN WITNESS whereof the parties hereto have hereunto set their hands and seals the day and year first above written.

Signed, sealed and delivered by from and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh.

In the presence of ;

- 1.
- 2.